

उत्तरांचल राज्य में वर्ष 2000-2001 में उपलब्ध होने वाली वनोपज-यूकेलिप्टस, खैर व कोमल काढ़ प्रजानियों का औद्योगिक इकाइयों को आवटन एवं मूल्य निर्धारण हेतु प्रमुख संघिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में आयोजित शीर्ष समिति की दिनांक 22.1.2001 को देहरादून में अहूत बैठक के कार्यवृत्।

उत्तरांचल शासन के कार्यालय ड्राफ सं0-92/वन एवं ग्राम्य विकास/वन/2000 दिनांक 30 दिसम्बर, 2000 द्वारा वनार्थीरित औद्योगिक इकाइयों को वनोपज के आवटन एवं मूल्य निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक का आयोजन वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त एवं वन उपयोग अधिकारी, उत्तरांचल के पत्रांक-1084/22-5 (कोमल काढ़), दिनांक 19.1.2001 द्वारा किया गया। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :-

1.	डा० आर० एस० टोलिया, प्रमुख संघिव, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल।	अध्यक्ष
2.	श्री० धी० सी० शर्मा संघिव, उद्योग, उत्तरांचल।	सदस्य
3.	श्री कौ० एन० सिंह, प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० वन निगम, लखनऊ	सदस्य
4.	श्री एन० कौ० जोशी, प्रमुख वन संरक्षक उत्तरांचल।	सदस्य
5.	श्री ठी० एस० तोमर, वन संरक्षक, शिवालिक एवं वन उपयोग अधिकारी, उत्तरांचल।	सदस्य संघिव

1.0 उत्तरांचल राज्य में औद्योगिक इकाइयों को वनोपज (काढ़ माल) के आवटन की यह प्रथम बैठक है। अतः बैठक की कार्यालयी आरम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से आये उनके प्रतिनिधियों के विचार सुने गये। बैठक में मैसर्स स्टार पेपर मिल्स, सहारनपुर, मै० विमको माचिस क०, बरेली, ए-वन ड्रेडिंग कारपोरेशन, हल्द्वानी, मै० नार्दन प्लाइस्टर, रामनगर, पर्वतीय प्लाइस्टर, काशीपुर आदि के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे य कठिनाइयों के बारे में समिति को बताया।

1.1 वनसंरक्षक (शिवालिक) एवं वन उपयोग अधिकारी, उत्तरांचल ने अपने पत्रांक-1091/22-5(कोमल काढ़), दिनांक 22.01.2001 द्वारा एजेण्डा मदों पर विचार-विमर्श हेतु एक टिप्पणी/नोट उपस्थित सदस्यों को उपलब्ध कराया।

1.2 प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल ने बैठक की कार्यवाही आरम्भ करते हुए समिति को औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल के आवंटन की प्रक्रिया के बारे में सक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने अवगत कराया कि वन विभाग द्वारा पेड़ों का छपान करके वन निगम को लौट आवृटित किये जाते हैं। वन निगम द्वारा इन वृक्षों का विदोहन करके औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकतानुसार वार्षिक नपतों में रूपान्तरण करके प्रकाष्ठ विक्रय डिपो पर लाया जाता है, जहां सं उद्योगों को निर्धारित मूल्य पर प्रकाष्ठ की आपूर्ति की जाती है।

### (क) यूकेलिप्टस:-

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल ने कागज की औद्योगिक इकाइयों को आवृटित होने वाली यूकेलिप्टस की मात्रा एवं मूल्य निर्धारण के विषय में समिति को यह अवगत कराया कि विगत वर्षों तक उत्तर-प्रदेश में पेपर मिलों द्वारा यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ का आवंटन एवं मूल्य निर्धारण प्रमुख संघिव, वन की अध्यक्षता में गठित शीष समिति द्वारा किया जाता रहा है। यूकेलिप्टस वी कुल उत्पादित मात्रा का 75% भाग दो पेपर मिलों यथा—मै0 सेन्चुरी पल्प एवं पेपर मिल्स लिं0, लालकुआ, तथा मै0 रस्टार पेपर मिल्स लिं0, सहारनपुर में बराबर-बराबर भाग में आवृटित किया जाता था। शेष 25% मात्रा में से 5000 घन मीटर यूकेलिप्टस का आवंटन मै0 घई इण्डस्ट्रीज, काशीपुर को करने के बाद अवशेष मात्रा खुले बाजार में बेची जाती थी।

### यूकेलिप्टस का मूल्य निर्धारण :-

वर्ष 1999-2000 के लिए यूकेलिप्टस का मूल्य रु0 2475/C प्रति वा0 मी0 टन निर्धारित था कार्यसूची में यह प्रस्ताव था कि वर्ष 2000-2001 के लिए भी यूकेलिप्टस का आवंटन मूल्य विगत वर्ष के बराबर अर्थात् रु0 2475/= प्रति वा0 मी0 टन रखा जाय। प्रबन्ध निदेशक ने अवगत कराया कि वन निगम को नीताम में रु0 2532/= प्रति वा0 मी0 टन का मूल्य प्राप्त हो रहा है। पेपर मिलों को पल्प ग्रेड प्रकाष्ठ आपूर्ति होता है, जिसका बक्कल उत्तरा जाता है। बक्कल उत्तरार्ने में रु0 25/= प्रति वा0 मी0 टन का अतिरिक्त व्यय आता है, जिसे जोड़कर रु0 2557/= प्रति वा0 मी0 टन की दर से आवंटन मूल्य रखा जाना सुनित होगा। प्रबन्ध निदेशक द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया गया कि बाजार में कागज के मूल्यों में हुई वृद्धि के आधार पर पेपर मिलों को कच्चे माल के लिए भुगतान की क्षमता में विवर वर्ष के सापेक्ष कुछ वृद्धि हुई है, अतः रु0 2557/= प्रति वा0 मी0 टन की दर पर भुगतान करने में पेपर मिलों को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

सम्पूर्ण विवारोपसन्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2000-2001 के लिए यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ का आवंटन मूल्य रु0 2557/= प्रति वा0 मी0 टन निर्धारित करने की संस्तुति उत्तरांचल सरकार से की जाये।

### यूकेलिप्टस का आवंटन :-

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल का प्रस्ताव था कि सर्वप्रथम इस बात का निर्णय कर लिया जाय कि क्या उत्तरांचल से बाहर की इकाइयों को आवंटन किया जाय या नहीं? प्रबन्ध निदेशक का मत था कि यूकेलिप्टस की व्यवस्था जो अभी तक लागू थी, उसी को बनाये रखा जाना चाहिये। यदि केवल सेन्चुरी पल्प एवं पेपर मिल को ही सारा यूकेलिप्टस आवृटित किया जाता है तो उनको एकाधिकार हो जायेगा और वह अपनी शर्तों पर वन विभाग व वन निगम को बाध्य कर सकते हैं। अप्पक्ष महोदय ने समिति को सूचित किया है कि सेन्चुरी पेपर मिल के प्रतिनिधि उनसे मिले थे, उन्होंने बताया कि उत्तरांचल राज्य के गठन के बाद काश्तकारों से प्राप्त होने वाली यूकेलिप्टस की लकड़ी अब उन्हें नहीं मिल पा रही है, क्योंकि यह क्षेत्र अधिकाशत उत्तर प्रदेश में आ गये हैं, अतः सेन्चुरी पेपर मिल की इस कमी की क्षतिपूर्ति होनी चाहिये। प्रमुख वन संरक्षक ने सुझाव दिया कि यदि सेन्चुरी पल्प एवं पेपर मिल तथा स्टार पेपर मिल्स के आवंटन अनुपात को क्रमशः 60:40 प्रतिशत कर दिया जाय तो सेन्चुरी की तथाकथित क्षति की कुछ सीमा तक पूर्ति हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उत्तरांचल राज्य के कुल यूकेलिप्टस का 75 प्रतिशत भाग दोनों पेपर मिलों यथा मै0 सेन्चुरी पल्प एवं पेपर मिल, लालकुआ तथा मै0 रस्टार पेपर मिल्स लिं0 सहारनपुर में 60:40 के अनुपात में आवृटित करने की संस्तुति शासन से की जाय। शेष 25% मात्रा में से ५० घई इण्डस्ट्रीज, काशीपुर को गत वर्षों की भाति 5000 घ0 मी0 यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ का आवंटन कर दिया जाय। मै0 घई इण्डस्ट्रीज के लिए आवंटन मूल्य विगत वर्ष की भाति ही रखा जाय जो पेपर मिलों के लिए निर्धारित किया गया है। यह मूल्य केवल पेपर पल्प ग्रेड के प्रकाष्ठ अर्थात् 21 से 60 सेमी० मध्य घेरी (बक्कल रहित) के लिए मूल्य रु0 100/= प्रति वा0 मी0 टन अधिक होगा। शेष मात्रा का निरस्तारण वन निगम अपने स्तर से सार्वजनिक नीताम के माध्यम से करे।

अध्यक्ष महोदय ने उपरोक्त प्रस्ताव पर सहमति घोषित करते हुए यह निर्देश दिये कि चूंकि पूर्व में खीर आवंटन करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट द्वारा लिया गया था, अतः अब आवंटन प्रक्रिया द्वन्द्व करके नीलाम करने का यह निर्णय भी उत्तराञ्चल कैबिनेट से लिया जाय। खीर का नीलाम उत्तर प्रदेश बन निगम अपनी नीलाम प्रक्रिया व निर्धारित नियमों/शर्तों के अन्तर्गत उसी प्रकार करेंगे जैसा कि अब तक बनोपज की नीलामी में अपनायी जा रही है। यह देख लिया जाय कि नीलामी में बाजार भाव के अनुसार विक्रय मूल्य अवश्य प्राप्त हो जायें।

#### 1.4- कौमल काष्ठ :-

हो। पॉपलर प्रकाष्ठ की आवंटन दरों के विषय में प्रबन्ध निदेशक द्वारा यह अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार पॉपलर प्रकाष्ठ की कुल उत्पादित मात्रा का 20 प्रतिशत भाग नीलाम करके, नीलाम में प्राप्त मूल्य को बाजार मूल्य मानकर आवंटन मूल्य निर्धारण किया जाय। वन निगम द्वारा तदनुसार उत्पादन वर्ष 2000-01 के कुल अनुमानित मात्रा के सभी श्रेणी के 20 प्रतिशत भाग की निविदायें आमंत्रित की गयी। निविदा में पॉपलर की 31-45 सेमी० गोलाई वर्ग के लिए ₹० 1455/- प्रति घन मीटर, 46-75 सेमी० गोलाई वर्ग के लिए ₹० 3118/- प्रति घन मी० तथा 75 सेमी० से ऊपर गोलाई वर्ग के लिए ₹० 3864/- प्रति घन मी० की दरें प्राप्त हुई हैं। अतः नीलामी से प्राप्त इन उच्चतम दरों के आधार पर श्रेणीवार आवंटन मूल्य निर्धारित करने पर विद्यार कर लिय जाय।

संप्राप्त इन उच्चतम दरों के जारी १८ सितंबर २००५ को विभिन्न विवरणों के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि निविदा दरों को बाजार भव मानत हुए वर्ष २०००-०१ के पॉपलर के ३१-४५ सेमी० व्यास वर्ग के लिए रु० १४६५/- प्रति घन मी०, ४५-७५ सेमी० गोलाई वर्ग के लिए रु० ३११०/- प्रति घन मी० तथा ७५ सेमी० से अधिक गोलाई वर्ग के लिए रु० ३८६४/- प्रति घन मी० की आवटन दर निर्धारित करने की सुस्ति उत्तरांचल सरकार से की जाय।

आवंटन की मात्रा के विषय में वन सरकार (शिवालिक) एवं वन उपयोग अधिकारी, उत्तराखण्ड हारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार शासन को संस्तुति करने का निर्णय लिया गया। गोलाईशर मात्रा का निर्धारण प्रबन्ध निदेशक, काठ

की उपलब्धता के आदार पर अपने स्तर से करेंगे।

## 20 अन्य विषय :-

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी घोरणा दिये गये कि आवटियों को आवटित मात्रा की प्रतिमूर्ति जमा कराने के लिए 15 दिनों का समय तथा माल उठाने के लिए 1 माह का समय दिया जाय। यदि नियासित अवधि में आवटियों द्वारा आवटित प्रकाष्ट की निकासी नहीं हो जाती है तो आवटन आदेश निरस्त मानते हुए अवशेष आवटित लेकिन न उठाये गये प्रकाष्ट का नीलाम "कैश एण्ड कैरी" विधि से निरस्तारित कर लिया जायेगा। इस व्यवस्था पर भी उत्तरांचल शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2.1- समिति द्वारा उक्त संस्थाओं पर उत्तरांचल सरकार का अनुमोदन प्राप्त करके शासन के जीपचारिक आदेश पृष्ठक से प्रसारित किये जायेंगे। इसके बाद ही आवटित प्रकाष्ट की मात्रा को आवटियों को रिलीज करने की कार्यवाही की जायेगी।

## 3-सम्पादन :-

अन्त में वैतक अध्यक्ष महोदय तथा रानी उपरिथित सदरभौं को धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

अनुमोदित

(डी० एस० चौपर)

दन सरकार,

शिवालिक वृत्त एवं पदेन

दन उपचोग अधिकारी

उत्तरांचल राज्य

(डा० आर० एस० टोलिया)

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

दन एवं ग्राम्य विकास

उत्तरांचल सरकार